दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित: 22.7.2009
आदेश की तिथि: 16.09.2009

मू.वि.या. सं. 267/2006

04.09.2009

डॉ. राम अवतार शर्मा **...अपीलार्थी**

द्वारा:श्री प्रेम कुमार, अधिवक्ता

बनाम

महाराजा अग्रसेन कॉलेज **.... प्रत्यर्थी**

द्वारा: श्री रमन कपूर, अधिवक्ता श्री मुनीश कुमार और श्री अमित कुमार, अधिवक्तागण

न्यायमूर्ति शिव नारायण ढींगरा

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ
2. संवाददाताओं के पास संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

निर्णय

1. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने अध्यादेश XII खंड 9(i) विश्वविद्यालय कैलेंडर के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा गठित एक अपील समिति द्वारा पारित 21 अप्रैल, 2006 के एक अधिनिर्णय को चुनौती दी है। अपील समिति में तीन सदस्य शामिल थे।

2. इस याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। शासी निकाय ने पाया कि प्रधानाचार्य/याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न अनियमितताएँ और कदाचार किए गए थे और उनके खिलाफ़ 23 आरोपों का आरोप पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ़ जाँच शुरू की गई। जाँच दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी गई थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ़ 23 में से 22 आरोप साबित नहीं हुए। 23वें आरोप में विभिन्न उपशीर्ष थे जिनमें 177 आरोप शामिल थे। कॉलेज के प्रस्तुतिकरण अधिकारी ने केवल 69 आरोप लगाए। इन 69 आरोपों में से, जाँच अधिकारी ने निष्कर्ष दिया कि 28 आरोप साबित नहीं हुए और शेष 41 आरोपों के विषय में, जाँच अधिकारी ने निम्नलिखित पाया:

- 17 आरोप इस हद तक साबित पाए गए कि इन आरोपों में संदर्भित खरीदारी करने या सिविल कार्यों को निष्पादित करने के लिए खुली निविदा पूछताछ आवश्यक थी - लेकिन उनका विज्ञापन नहीं किया गया था। वास्तव में, चार्ज 3.5.4 के संबंध में, यह नोट किया गया है कि कोई खुली निविदा पूछताछ नहीं हुई थी और बुलाए गए सीमित कोटेशन भी केवल दिखावा के लिए थे।
- 9 मामले इस हद तक साबित पाए गए कि बिना किसी कोटेशन की माँग किए खरीदारी की गई या सिविल कार्यों का आदेश दिया गया।
- सिविल कार्यों के लिए खरीद/ऑर्डर के 15 मामलों में कोटेशन बुलाए गए - लेकिन उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। विचार हेतु कोटेशन खोले जाने से पहले ही खरीद कर ली गई थी या सिविल कार्य करा लिया गया था। जाँच प्राधिकरण ने पाया कि "कोटेशन केवल दिखावे के तौर पर या ढकोसले के तौर पर पेश किए गए थे।"

3. जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने/बर्खास्तगी के दंड का प्रस्ताव रखा और याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया। याचिकाकर्ता ने जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रबंधन समिति द्वारा उसे सेवा से हटाने पर आपत्ति जताई। विश्वविद्यालय कैलेंडर के अध्यादेश XII के तहत कुलाधिपति द्वारा एक अपील समिति का गठन किया गया था। अपील समिति के समक्ष याचिकाकर्ता ने लगभग वही रुख अपनाया था जो याचिकाकर्ता ने अपील समिति के अधिनिर्णय

को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष अपनाया था। अपील समिति याचिकाकर्ता की विभिन्न दलीलों पर विस्तार से विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँची कि 41 उपशीर्षों के मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ़ आरोपों को जाँच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य और सामग्री के आधार पर सही साबित किया गया और दिया गया दंड याचिकाकर्ता के आचरण के अनुरूप थी।

4. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर अपील समिति के अधिनिर्णय को चुनौती दी हैः

i) जाँच सही नहीं थी क्योंकि याचिकाकर्ता को यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि किस नियम/अध्यादेश के तहत जाँच की जा रही थी और प्रस्तावित कार्रवाई की जानी थी। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन हुआ है।

ii) याचिकाकर्ता को यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कें.सि.से. (वर्गी.नि.अ.) आचार नियम याचिकाकर्ता पर लागू होते हैं या नहीं।

iii) याचिकाकर्ता के खिलाफ़ लगाए गए आरोप अस्पष्ट प्रकृति के थे और उनमें आवश्यक सामग्री विवरण शामिल नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को नहीं पता था कि उसे कौन से आरोपों का सामना करना है।

iv) जाँच के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ़ मामला प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का साबित हुआ, न कि अवैधताओं का, इसलिए सेवा से हटाने का बड़ा जुर्माना अवांछनीय था और याचिकाकर्ता को केवल कोई मामूली जुर्माना दिया जा सकता था।

v) शासी निकाय द्वारा स्वीकार की गई जाँच रिपोर्ट से पता चलता है कि आरोप पत्र के तहत की गई खरीदारी के कारण कॉलेज को कोई हानि नहीं हुई थी और याचिकाकर्ता की ओर से कोई दुर्भावना साबित नहीं हुई थी। खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता वास्तविक आवश्यकता से कम या अधिक नहीं पाई गई। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के कृत्य प्रामाणिक और कॉलेज के समग्र हित में थे। जाँच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य पद से हटाना अनुचित था।

vi) तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट, जो जाँच शुरू करने का आधार थी, याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई।

vii) कॉलेज के लिए की जाने वाली खरीदारी में उचित प्रक्रिया का पालन करना क्रय समिति का कार्य था। प्रधानाचार्य होने के नाते याचिकाकर्ता को क्रय समिति के कृत्यों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता के बजाय क्रय समिति के सदस्यों को अपना आचरण स्पष्ट करना चाहिए था।

viii) यह क्रय समिति थी जिसे "अत्यावश्यक प्रमाणपत्र" जारी करना था, न कि प्रधानाचार्य को, जैसा कि जाँच अधिकारी और अपील समिति ने निष्कर्ष निकाला था।

ix) याचिकाकर्ता के खिलाफ़ वित्तीय अनियमितता करने का कोई आरोप तय नहीं किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने कोई कदाचार किया है।

x) याचिकाकर्ता के खिलाफ़ आरोप सं. 3 के तहत 41 उप आरोप साबित होने के बावजूद जाँच रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि याचिकाकर्ता ने सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

xi) याचिकाकर्ता के खिलाफ़ तय किया गया आरोप सं. 3 बहुत अस्पष्ट और मौन था कि याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रचलित किन नियमों, प्रक्रियाओं और विनियमों का उल्लंघन किया गया था। आरोप सं. 3 में सामान्य वित्तीय नियमों का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए जाँच प्राधिकरण 41 आरोपों में से आरोप सं. 3 के उप-शीर्षों के तहत एक निष्कर्ष वापस नहीं कर सका।

xii) राशि, तिथियों और पक्षों के संबंध में शुल्कों में कई खामियाँ और विसंगतियाँ थीं और शुल्कों और दिए गए दस्तावेज़ों के बीच कोई सह-संबंध नहीं था। इसलिए आरोपों की अस्पष्टता के कारण जाँच सही नहीं थी।

अपील समिति ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया कि आरोप-पत्र दोषपूर्ण था। अपील समिति आरोप पत्र में खामियों पर विचार करने में विफल रही और याचिकाकर्ता पर यह दिखाने का बोझ डालकर मुद्दे को टाल दिया कि क्या ऐसी खामियों के कारण कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ है या आरोप गलत साबित हुए हैं।

xiii) अपील समिति ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया कि याचिकाकर्ता के मामले में विश्वविद्यालय कैलेंडर का अध्यादेश XII लागू नहीं था और इस मामले में अध्यादेश XVIII लागू होना था। अध्यादेश XVIII में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि प्रधानाचार्य की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा 'कदाचार' के लिए निर्धारित की जा सकती है, लेकिन 'अच्छे कारण' को छोड़कर निर्धारित नहीं की जाएगी। शासी निकाय ने अध्यादेश XVIII के इन दो बुनियादी तत्वों को नज़रअंदाज़ कर दिया और अपील समिति ने भी इसे नज़रअंदाज़ कर दिया। याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य पद से हटाने का कोई पर्याप्त या उचित कारण नहीं था।

xiv) अपील समिति और जाँच अधिकारी ने दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम 1922 के विपरीत कार्य किया। दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत, विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी और कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और वित्त समिति के

पदेन अध्यक्ष होने के नाते, यह देखने का कर्तव्य कुलाधिपति का है कि अध्यादेश या विनियमों का विधिवत रूप से पालन किया जाए और यह कुलाधिपति ही है जो प्रधानाचार्य के खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। याचिकाकर्ता के साथ अध्यादेश XII के तहत गलत व्यवहार किया गया। याचिकाकर्ता के साथ अध्यादेश XVIII के तहत कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता थी, जिसमें प्रावधान था - "भारत सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों के अलावा अन्य कॉलेज", और चूँकि महाराजा अग्रसेन कॉलेज भारत सरकार द्वारा संचालित नहीं था, इसलिए यहाँ केवल अध्यादेश XVIII लागू होता, न कि अध्यादेश XII. अध्यादेश XVIII के तहत कॉलेज के शासी निकाय में निलंबन या समाप्ति की कोई शक्ति निहित नहीं है।

xv) शासी निकाय अध्यादेश XVIII के तहत कार्यकारी परिषद की मंज़ूरी के अधीन प्रधानाचार्य की नियुक्ति कर सकता है, इस प्रकार, परिणाम के रूप में, प्रधानाचार्य को केवल कार्यकारी परिषद की मंज़ूरी के साथ हटाया जा सकता है और शासी निकाय के पास प्रधानाचार्य की सेवाओं को स्वयं समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं है।

xvi) अपील समिति गलत आचरण करने और बुनियादी मुद्दे पर विचार नहीं करने की गंभीर गलती में फँस गई कि क्या सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया गया था या नहीं।

xvii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी परिपत्र सं. एफ़-डी.ई.-27(45)96-97/सी.बी./शि./1438-49 दिनांक 06.06.1997 पर निर्भर करते हुए कॉलेज प्रधानाचार्य पर संहितागत औपचारिकताओं का कड़ाई से पालन करने, सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का पालन करने, अनुदान की शर्तें और अनुदान के उपयोग के संबंध में दिल्ली सरकार के निर्देश/सलाह पर अपील समिति द्वारा गलत तरीके से निर्भर किया गया, जिससे याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के साथ गंभीर अन्याय हुआ। ऐसे परिपत्र की कोई विधिक मंज़ूरी नहीं थी। चूँकि, यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम किया था या संस्था को वित्तीय हानि पहुँचाई थी, वित्तीय नियमों का पालन न करना कदाचार नहीं माना जा सकता है।

xviii) सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन याचिकाकर्ता को कदाचार का दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता। सामान्य वित्तीय नियमों को कभी भी याचिकाकर्ता की सेवा शर्तों का हिस्सा नहीं माना गया, सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन कदाचार को आकर्षित नहीं कर सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थान था और भारत सरकार का कोई भी नियम दिल्ली विश्वविद्यालय और

उससे संबद्ध कॉलेज पर लागू नहीं होता था। महाराज अग्रसेन कॉलेज सोसायटी पर सामान्य वित्तीय नियम नहीं थोपे जा सकते। कॉलेज की अपनी खरीद प्रक्रिया थी जिसे शासी निकाय द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था।

xix) अपील समिति ने अत्यधिक तकनीकी और कानूनी तरीके से कार्य किया। चूँकि याचिका के खिलाफ़ कॉलेज को कोई हानि या धन का दुरुपयोग साबित नहीं हुआ, इसलिए निम्नलिखित प्रक्रिया में अनियमितताओं को कदाचार नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता चेक जारी करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं में से केवल एक था, अन्य हस्ताक्षरकर्ता कॉलेज के कोषाध्यक्ष थे।

xx) जैसा कि जाँच प्राधिकरण ने देखा, रिकॉर्ड पर अनुचित प्रभाव के बारे में कोई विशेष सबूत नहीं था। खुली निविदा पूछताछ के लिए प्रधानाचार्य को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था और यह अनुभाग अधिकारी (लेखा) की ज़िम्मेदारी थी, तकनीकी त्रुटि, यदि कोई थी, तो अनु.अधि. (लेखा) और कोषाध्यक्ष की लापरवाही के कारण थी। याचिकाकर्ता को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अपील समिति ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया और उस अनु.अधि. (लेखा) को भी नज़रअंदाज़ कर

दिया, जो रिकॉर्ड का संरक्षक था और उसने अपनी जान बचाने के लिए मिथ्या और काल्पनिक तिथियाँ डालकर रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की थी।

xxi) अपील समिति इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती थी कि प्रधानाचार्य को अनु.अधि. (लेखा) और कोषाध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाना था और याचिकाकर्ता को अनु.अधि. (लेखा)/कोषाध्यक्ष के कृत्यों/चूक के लिए ज़िम्मेदार ठहराकर दंडित नहीं किया जा सकता था।

xxii) जाँच समिति ने यह देखने में गलती की कि नियमों के अनुपालन में बार-बार और लगातार विचलन और चूक हुई हैं। जाँच समिति ने याचिकाकर्ता को हटाए जाने पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को दिए गए दंड को पूरी तरह से असंगत माना।

xxiii) कुलाधिपति ने कदाचार को परिभाषित किए बिना, जो कि एक केंद्रीय मुद्दा था, याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य पद से हटाने को अपनी मंज़ूरी दे दी। कुलाधिपति द्वारा विवेक का उपयोग नहीं किया गया, जिन्होंने यह परिभाषित किए बिना कि कदाचार क्या होता है, प्रक्रियात्मक नियमों के उल्लंघन को कदाचार के रूप में गलत समझ लिया।

xxiv) यह अधिनिर्णय भारत की सार्वजनिक नीति और भारत में लागू सेवा न्यायशास्त्र की विधि के खिलाफ़ था।

5. अपील समिति के अधिनिर्णय को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों पर विचार करने के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि जाँच में याचिकाकर्ता के खिलाफ़ क्या आरोप साबित हुए। संक्षेप में, आरोपों के विभिन्न उप-शीर्षों और जाँच समिति के अवधारण निम्नानुसार है:

आरोप सं. 3.3.3

यह आरोप मैसर्स भारद्वाज एंड एसोसिएट्स द्वारा 1,18,108/- रुपये की कीमत पर क्लास रूम के निर्माण के संबंध में था। याचिकाकर्ता के खिलाफ़ अभियोग यह था कि कोई कोटेशन नहीं माँगी गई थी, निर्माण समिति फ़र्म को इस काम का ऑर्डर देने में शामिल नहीं थी और कॉलेज के शासी निकाय की कोई मंज़ूरी नहीं थी। जाँच समिति ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ़ उक्त आरोप साबित हुआ है क्योंकि सीमित जाँच के माध्यम से भी निविदा/कोटेशन मँगाने की आवश्यकता याचिकाकर्ता द्वारा नहीं माँगी गई थी।

आरोप सं. 3.3.7

यह आरोप मैसर्स भारद्वाज एंड एसोसिएट्स द्वारा 16,335/- रुपये के विद्युत कार्य से संबंधित है। आरोप यह था कि इस कार्य के लिए कोई कोटेशन आमंत्रित नहीं की गई, क्रय समिति को भी इसमें शामिल नहीं किया गया और शासी निकाय की मंज़ूरी के बिना ही कार्य करा लिया गया। इसके अलावा ठेकेदार के पास कोई अनुभव नहीं था और न ही काम का सत्यापन किया गया था। यह आरोप भी स्थापित किया गया था क्योंकि कोटेशन आमंत्रित किया जाना चाहिए था और इसे क्रय समिति के

माध्यम से भेजा जाना चाहिए था। खरीद की वित्तीय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ था।

आरोप सं. 3.4.1

यह आरोप दीवार वाले श्यामपट्ट के कार्य से संबंधित है। आरोप में अभियोग लगाया गया कि न तो कोई कोटेशन मँगाई गई थी और न ही निर्माण समिति से कोई अनुशंसा ली गई और बिना शासी निकाय की मंज़ूरी के काम दे दिया गया और काम का सत्यापन भी नहीं किया गया। यह पाया गया कि कोटेशन न मँगाने में वित्तीय नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ था। उक्त आरोप उक्त सीमित सीमा तक साबित हुआ।

आरोप सं. 3.4.2

यह आरोप मैसर्स भारद्वाज एंड एसोसिएट्स द्वारा किए गए सिविल कार्य से संबंधित है। अभियोग यह था कि तीन में से दो कोटेशन असली नहीं थे, कोई सत्यापन नहीं किया गया था, निर्माण समिति काम की अनुशंसा में शामिल नहीं थी और शासी निकाय की मंज़ूरी के बिना काम करवाया गया था। अभियोग 'खुली निविदा' आमंत्रित नहीं करने से संबंधित है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोटेशन प्राप्त न करना वित्तीय प्रक्रिया का उल्लंघन था। संस्थान का प्रमुख होने के नाते याचिकाकर्ता की ज़िम्मेदारी वित्तीय प्रक्रियाओं को लागू करना और उनका पालन करना था, जो नहीं किया गया और एक चूक हुई है।

आरोप सं. 3.4.4

यह आरोप कॉलेज में मरम्मत से संबंधित है। आरोप है कि प्राप्त तीन में से दो कोटेशन असली नहीं थे और निर्माण समिति से सलाह नहीं ली गई। यह पाया गया कि बिल ठेकेदार के नाम की अनुशंसा और कोटेशन खोलने से पहले की तिथि के थे। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि कोटेशन पर विचार करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और याचिकाकर्ता प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार था।

आरोप सं. 3.4.5

यह आरोप कंप्यूटरों की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह है कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे। यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्रय में प्रक्रियात्मक अनियमितता की गई थी और याचिकाकर्ता का कर्तव्य था कि उसे पता चले कि कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया गया और आपूर्ति का आदेश क्रय प्रक्रिया का पालन किए बिना दिया गया था।

आरोप सं. 3.4.10

यह आरोप कॉलेज में निर्माण कार्य से संबंधित है। अभियोग यह है कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे। यह अभिनिर्धारित किया गया कि काम बिना कोटेशन के किया गया था और भुगतान अन्य बिलों के साथ जोड़ दिया गया था। कोटेशन न मँगाना सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन था। इस हद तक यह आरोप स्थापित हो गया।

आरोप सं. 3.4.15

यह आरोप प्रिंटमेन से किताबें खरीदने से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे। यह स्थापित किया गया कि किताबें खरीदने में निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन हुआ था। याचिकाकर्ता की ज़िम्मेदारी यह देखना था कि आपूर्ति का आदेश देने से पहले कोटेशन पर विचार किया गया है या नहीं।

आरोप सं. 3.5.1

यह आरोप मैसर्स कॉमकैट से कंप्यूटर और अन्य हिस्सों की खरीद से संबंधित है। अभियोग था कि कोटेशन नहीं मँगाई गई, क्रय समिति के माध्यम से खरीद नहीं कराई गई। यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता ने कोषाध्यक्ष की अनुशंसा के बिना बिलों को मंज़ूरी दे दी। इन खरीदों के बारे में सामान्य वित्तीय नियमों के उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ता की ज़िम्मेदारी स्थापित की गई थी।

आरोप सं. 3.5.3

यह आरोप ऑसिलोस्कोप आदि की खरीद को लेकर था। अभियोग यह था कि आवश्यकतानुसार कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई और क्रय समिति द्वारा निविदाओं पर विचार नहीं किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध की गई तात्कालिकता को उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उक्त तात्कालिकता के बारे में कोई प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किया गया था और इसके अभाव में, खुली निविदा पूछताछ अनिवार्य थी। प्रक्रिया का उल्लंघन स्थापित हो गया।

आरोप सं. 3.5.4

यह आरोप मेज-कुर्सियों की खरीद को लेकर था। अभियोग यह था कि खुली निविदा पूछताछ प्रणाली का पालन नहीं किया गया, तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे और खरीदारी क्रय समिति के माध्यम से नहीं की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि खुली निविदा पूछताछ जारी करने की आवश्यकता थी लेकिन जारी नहीं की गई। प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ और याचिकाकर्ता इसके लिए ज़िम्मेदार था।

आरोप सं. 3.6.2

यह आरोप कंप्यूटर स्टेशनरी की खरीद को लेकर था। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे। आरोप एक सीमित सीमा तक स्थापित किया गया था कि क्रय समिति खरीद से पहले खरीद में शामिल नहीं थी।

आरोप सं. 3.7.1

आरोप ए.बी.सी. इंटरप्राइज़ेस से हार्ड बाउंड रजिस्टर की छपाई को लेकर था। अभियोग यह था कि तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे। यह अभिनिर्धारित किया गया कि माल की आपूर्ति के बाद कोटेशन केवल नकली कोटेशन के रूप में डिफ़ॉल्ट को पूरा करने के लिए प्राप्त किए गए थे। आरोप सिद्ध पाया गया।

आरोप सं. 3.8.7

यह पुस्तक केस की खरीद से संबंधित था। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था। यह पाया

गया कि कोटेशन और क्रय समिति की अनुशंसा पर विचार किए बिना खरीद की गई और सामान्य वित्तीय नियमों की प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ।

आरोप सं. 3.8.15

यह चार्ज वाटर कूलर की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और चार में से तीन कोटेशन वास्तविक नहीं थे। अपील समिति ने कहा कि वाटर कूलर की आपूर्ति के चालान और भुगतान के चेक पर कोटेशन की तिथि से पहले की तिथियाँ अंकित थीं। इस प्रकार कोटेशनों को ढोंग माना गया।

आरोप सं. 3.9.5

यह आरोप टेबल-कुर्सियों की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे और ऑर्डर देने से पहले कोटेशन भी नहीं खोले गए थे और कोई खुली निविदा पूछताछ प्रणाली का पालन नहीं किया गया था और शासी निकाय से कोई मंज़ूरी नहीं ली गई थी। आरोप इस हद तक सिद्ध हुआ कि खरीद 'सीमित निविदा जाँच' के माध्यम से की गई थी जबकि इसे खुली निविदा पूछताछ के आधार पर किया जाना चाहिए था।

आरोप सं. 3.10.2

यह आरोप स्टील की अलमारियों की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय की कोई मंज़ूरी नहीं थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोटेशन आमंत्रिक करना अर्थहीन था क्योंकि खरीद कोटेशन देखे बिना ही की गई थी।

आरोप सं. 3.10.3

यह आरोप लैब उपकरणों की खरीद से संबंधित था। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय की कोई मंज़ूरी नहीं थी और यह भी कि अनिवार्य होने के बावजूद कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि खरीदारी 50,000/- रुपये से अधिक के लिए की गई थी और एक खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित की जानी चाहिए थी, हालाँकि, केवल एक सीमित निविदा जाँच की गई थी। इस हद तक सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ। याचिकाकर्ता को सामान्य वित्तीय नियमों के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया था।

आरोप सं. 3.10.4

यह आरोप प्रयोगशाला मेज की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति शामिल नहीं थी और चार में से तीन कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय की कोई मंज़ूरी नहीं थी और कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी। आरोप इस हद तक साबित हुआ कि खुली निविदा पूछताछ प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और क्रय समिति या किसी अन्य द्वारा सीमित कोटेशन पर भी विचार किए बिना खरीदारी की गई।

आरोप सं. 3.10.7

यह आरोप कुर्सियों की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति शामिल नहीं थी और चार में से तीन कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय की कोई मंज़ूरी नहीं थी और कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि खुली

निविदा पूछताछ अनिवार्य थी। सामान्य वित्तीय नियमों के तहत आवश्यकतानुसार इसका विज्ञापन नहीं किया गया था। इस हद तक सामान्य वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था।

आरोप सं. 3.10.9

यह आरोप रेज़िस्टेंस बॉक्स और प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद से संबंधित था। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और कोई कोटेशन नहीं मँगाई गई थी और शासी निकाय की मंज़ूरी नहीं थी। यह आरोप इस हद तक स्थापित किया गया था कि खरीद में सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता ने इस संबंध में चूक की थी।

आरोप सं. 3.10.10

यह आरोप कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और चार में से तीन कोटेशन वास्तविक नहीं थे और कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ था और खुली निविदा पूछताछ की माँग की गई होगी। याचिकाकर्ता यह देखने के लिए ज़िम्मेदार था कि खरीदारी सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार थी और खामियों के लिए उसे ज़िम्मेदार ठहराया गया था।

आरोप सं. 3.11.3

यह आरोप प्रिंटर की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और कोई कोटेशन आमंत्रित नहीं की गई थी। आरोप इस हद तक स्थापित किया गया कि खरीद के लिए कोई

कोटेशन नहीं बुलाई गई और सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ।

आरोप सं. 3.11.5

यह आरोप जनरेटर की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और चार में से तीन कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय की कोई मंज़ूरी नहीं थी और कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी। आपूर्ति और बिल और भुगतान का आदेश देने वाला पत्र एक ही तिथि का है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि खुली निविदा पूछताछ शुरू की जानी चाहिए थी और याचिकाकर्ता की ओर से चूक हुई थी।

आरोप सं. 3.11.6

यह आरोप माइक्रो प्रोसेसर किट की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और चार में से तीन कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय का कोई अनुमोदन नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूँकि वस्तुओं की खरीद 50,000/- रुपये से अधिक की थी, इसलिए एक खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई और सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ।

आरोप सं. 3.11.11

यह आरोप कॉन्फ्रेंस रूम के लिए गोल मेज की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति शामिल नहीं थी और चार में से तीन कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय का कोई अनुमोदन नहीं था

और कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि खुली निविदा पूछताछ की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई। याचिकाकर्ता को ज़िम्मेदार ठहराया गया।

आरोप सं. 3.11.13

यह आरोप एयर कंडीशनर की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह है कि क्रय समिति शामिल नहीं थी और चार में से तीन कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय का कोई अनुमोदन नहीं था और कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता ने तत्काल अनुरोध किया। हालाँकि, तात्कालिकता का कोई प्रमाण पत्र वहाँ नहीं था और न ही रिकॉर्ड पर रखा गया था। 50,000/- रुपये से अधिक की खरीद के लिए खुली निविदा पूछताछ आवश्यक थी, जो नहीं की गई। याचिकाकर्ता को सामान्य वित्तीय नियमों के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया था।

आरोप सं. 3.12.4

यह आरोप कार्यालय स्टेशनरी की छपाई से संबंधित था। अभियोग यह था कि क्रय समिति शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय का कोई अनुमोदन नहीं था और कोई खुली निविदा पूछताछ नहीं की गई थी। मानक खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया और कोई भी कोटेशन वास्तविक साबित नहीं हुआ।

आरोप सं. 3.12.5

यह आरोप स्टील रैक की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे। सामान्य वित्तीय नियमों की खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। क्रय

समिति की कोई पूर्व अनुशंसा नहीं थी। याचिकाकर्ता को इस हद तक सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने में शामिल पाया गया।

आरोप सं. 3.16.1

यह आरोप वर्ष 1996-97 के दौरान मैसर्स भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के माध्यम से कराए गए विविध कार्यों के लिए विकास निधि से किए गए व्यय से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति को शामिल नहीं किया गया और कोई कोटेशन नहीं मँगाया गया था। सामान्य वित्तीय नियमों की खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। सीमित निविदा पूछताछ द्वारा कोटेशन/निविदा मँगाने की आवश्यकता थी, हालाँकि इसका पालन नहीं किया गया।

आरोप सं. 3.18.2

यह आरोप मैसर्स संजय डीज़ल्स से विभिन्न वस्तुओं की खरीद से संबंधित है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्रय समिति और प्रधानाचार्य द्वारा उचित विचार-विमर्श और कोटेशन की तुलना के बाद खरीद की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया था। क्रय समिति से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था।

आरोप सं. 3.18.5

यह आरोप फ़ॉल्स सीलिंग लगाने से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय का कोई अनुमोदन नहीं था। बिना किसी कोटेशन का संदर्भ लिए ठेका दे दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया था।

आरोप सं. 3.18.6

यह आरोप मैसर्स भारद्वाज सर्विसिंग द्वारा किए गए विविध कार्यों से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय का कोई अनुमोदन नहीं था और कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया था क्योंकि कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी, भले ही खरीद 50,000/- रुपये से अधिक थी। इस हद तक याचिकाकर्ता को ज़िम्मेदार ठहराया गया।

आरोप सं. 3.18.7

यह आरोप कंप्यूटर और प्रिंटर के लिए सर्वर की खरीद से संबंधित था। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे और कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया था क्योंकि कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी, बावजूद इसके कि खरीद 50,000/- रुपये से अधिक की थी। याचिकाकर्ता, जिसने खुली निविदा पूछताछ नहीं करने के लिए तत्काल आग्रह किया था, ने कोई प्रमाण पत्र या तात्कालिकता नहीं दी या दर्ज नहीं की और इसलिए उसे प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया।

आरोप सं. 3.19.2 और 3.19.5

ये आरोप बागवानी और विकास कार्यों से संबंधित थे। अभियोग यह था कि बागवानी समिति/क्रय समिति द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की गई थी और

कोई कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया था और खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा खुली निविदा पूछताछ आवश्यक होने के बावजूद कोटेशन या निविदाएँ आमंत्रित नहीं करने को सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना गया था।

आरोप सं. 3.19.6

यह आरोप कंप्यूटर और उसके हिस्सों की खरीद से संबंधित है। अभियोग यह था कि क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे और शासी निकाय से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था और कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया था क्योंकि कोई खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित नहीं की गई थी, बावजूद इसके कि खरीद 2,00,000/- रुपये से अधिक की थी। इस हद तक याचिकाकर्ता को ज़िम्मेदार ठहराया गया।

आरोप सं. 3.20.1

यह आरोप कॉलेज की नई साइट पर दो कमरे और शौचालय के निर्माण से संबंधित है। अभियोग यह था कि कोटेशन खोलने की कोई तिथि नहीं थी, न ही कोई ऑर्डर दिया गया था और शासी निकाय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से भी कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था और तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे। साथ ही कोटेशन से अधिक का भुगतान कर दिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि खुली निविदा पूछताछ आवश्यक थी क्योंकि कार्य 2,00,000/- रुपये से अधिक का था और यह सिविल कार्य की वित्तीय प्रक्रिया का उल्लंघन था।

6. याचिकाकर्ता के तर्कों और संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा गठित अपील समिति/अधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँची:

क) इस मामले में तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी क्योंकि तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट का आधार बनने वाली सभी ईएलएफ़ए रिपोर्टें याचिकाकर्ता को प्रदान की गई थीं। याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में असमर्थ था कि जिन आरोपों को सिद्ध माना गया था, उन्हें तथ्य खोज रिपोर्ट द्वारा कैसे समर्थित किया गया था। आरोप (जैसे कि साबित हुए हैं) अन्य दस्तावेज़ों और स्वीकृतियों के आधार पर साबित किए गए थे, न कि तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट के आधार पर। इस प्रकार, तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति ने जाँच को दूषित नहीं किया।

ख) याचिकाकर्ता, एक कॉलेज नियुक्त शिक्षक होने के नाते अध्यादेश XII द्वारा शासित था। अध्यादेश XII कॉलेज द्वारा नियुक्त शिक्षकों से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि शिक्षक में कॉलेज का प्रधानाचार्य भी शामिल होता है। अध्यादेश XII का खंड 3 कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में स्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति की सेवानिवृत्ति की आयु को संदर्भित करता है। खंड 6 निलंबन के तहत रखे गए 'प्रधानाचार्य' या 'शिक्षक' दोनों को संदर्भित करता है और खंड 9 कॉलेज

में नियुक्त शिक्षकों (प्रधानाचार्य सहित) की सेवाओं की समाप्ति के संबंध में विवाद के संबंध में एक अपील समिति की मध्यस्थता को संदर्भित करता है। जिस अपील समिति के समक्ष याचिकाकर्ता ने अपील की थी, वह स्वयं अध्यादेश XII के खंड 9 के तहत गठित की गई थी। अध्यादेश XII और XVIII के प्रावधानों के बीच काफ़ी अतिव्याप्ति थी। अपील समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि वास्तविक मुद्दा अध्यादेश XII या अध्यादेश XVIII की प्रयोज्यता नहीं है, बल्कि क्या अपीलकर्ता (यहाँ याचिकाकर्ता) पर लगाया गया जुर्माना अत्यधिक था और क्या कोई अन्य जुर्माना लगाने पर विचार करने के लिए शासी निकाय के पास विकल्प उपलब्ध थे। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अध्यादेश XII याचिकाकर्ता पर काफ़ी हद तक लागू था क्योंकि अध्यादेश XII एक प्रधानाचार्य सहित कॉलेज नियुक्त शिक्षक के संबंध में लागू था और याचिकाकर्ता ऐसे ही एक प्रधानाचार्य थे।

ग) केंद्रिय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में अपील समिति ने पाया कि नियम केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के स्थापन थे जो घरेलू जाँच पर लागू होते हैं और जब तक जाँच में अपनाई गई प्रक्रिया को मोटे तौर पर इन नियमों के अनुरूप माना जा सकता है, तब तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को उचित अवसर से वंचित कर दिया गया है।

घ) अस्पष्टता और दोषपूर्ण आरोपों के संबंध में, अपील समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि कथित दोष और अस्पष्टता गलत थी और मौजूद नहीं थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ़ साबित हुए सभी आरोप बहुत स्पष्ट थे। अपील समिति ने पाया कि न केवल आरोपों में साबित अवसरों पर सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ था, बल्कि याचिकाकर्ता के मामले में कई वर्षों से वित्तीय प्रक्रियाओं का आदतन उल्लंघन स्थापित किया गया था और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता था। कॉलेज के पूरे जीवनकाल में आकस्मिक खरीदारी और कार्य आदेश देने की स्थिति नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता, जो कि नियमों के तहत ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत कॉलेज का प्रधानाचार्य था, द्वारा कोई तात्कालिक प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के बावजूद एक भी खुली निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा कॉलेज शाखा निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र सं. एफ़-डी.ई.-27(45)/96-97/सी.बी./शि./1438-49 दिनांक 6.6.1997 के माध्यम से याचिकाकर्ता सहित प्रधानाचार्यों को सूचित किया था कि सामान्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यह याचिकाकर्ता के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था। सार्वजनिक धन से जुड़ी वित्तीय प्रक्रियाओं का आदतन उल्लंघन ही कदाचार है, भले ही आरोप-पत्र में विशेष रूप से "कदाचार" शब्द का उपयोग नहीं किया गया हो। शासी निकाय के पास दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित खरीद

प्रक्रिया में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि दिल्ली सरकार निधि प्रदाता थी। वित्तीय नियमों के अनुपालन के संबंध में दिल्ली सरकार के परिपत्र की एक प्रति याचिकाकर्ता को विशेष रूप से पृष्ठांकित की गई थी। इन नियमों की प्रयोज्यता याचिकाकर्ता के लिए स्पष्ट रही होगी। परिपत्र में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुदान का उपयोग करते समय सभी संहितागत औपचारिकताओं, सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों, अनुदान के निबंधनों और शर्तों और दिल्ली सरकार के निर्देशों/सलाह के कड़ाई से अनुपालन के लिए ज़िम्मेदार होंगे। प्रधानाचार्यों को अनुदान का उपयोग केवल निर्दिष्ट और अनुमोदित व्यय के लिए करना था और किसी भी विचलन के लिए वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होने थे। जिस समय याचिकाकर्ता प्रधानाचार्य थे, उस समय यह कॉलेज 100% दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/प्रायोजित कॉलेज था। इसलिए याचिकाकर्ता इस परिपत्र से आबद्ध थे जो एक सार्वजनिक दस्तावेज़ था। कॉलेज पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले वित्तीय लेनदेनों पर सामान्य वित्तीय नियमों की प्रयोज्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था। खुली निविदा प्रक्रिया से विचलन केवल तात्कालिकता प्रमाणपत्र की रिकॉर्डिंग से संबंधित सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रावधानों का पालन करके ही किया जा सकता है। ऐसे प्रमाणपत्र को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि असद्भाव का कोई सबूत न हो। हालाँकि, इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा

किसी भी खरीद के लिए किसी भी स्तर पर तात्कालिकता का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था और इसके बावजूद 41 शीर्षों के आरोपों के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमों के तहत आवश्यक सभी संहितागत औपचारिकताएँ नज़रअंदाज़ कर दी गईं।

ङ) अपील समिति ने पाया कि कॉलेज को हुई वित्तीय हानि या हानि की मात्रा का परीक्षण करने के लिए जाँच शुरू नहीं की गई थी। खरीद प्रक्रिया में गंभीर खामियों के संबंध में आरोप लगाए गए थे और इन्हें दस्तावेज़ी सबूत के साथ-साथ अपीलकर्ता (यहाँ याचिकाकर्ता) की स्वीकृति के आधार पर स्थापित किया गया था। अपील समिति ने नोट किया कि जाँच प्राधिकरण ने 15 उपशीर्षों (साबित) के संबंध में आरोप पर विचार किया था, जिसमें आमंत्रित कोटेशन पर विचार किए बिना "खरीदारी की गई थी या सिविल कार्य किए गए थे"। इन सभी मामलों में, कोटेशन विचार के लिए खोले जाने से पहले ही खरीदारी कर ली गई थी या सिविल कार्य पूरा कर लिया गया था। अपील समिति ने जाँच प्राधिकरण द्वारा विचार की गई सामग्री का अध्ययन किया और पाया कि जाँच प्राधिकरण द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि कोटेशन को अनियमितताओं पर पर्दा डालने के लिए एक प्रदर्शन वस्तु या 'धोखा' के रूप में पेश किया गया था, 'न्यायपूर्ण और सही' था। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता, जो प्रधानाचार्य थे, अपने द्वारा अनुमोदित बिलों या किसी भी खरीद दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथि न डालने

के लिए जाँच प्राधिकरण को कोई स्पष्टीकरण या ठोस कारण नहीं दे सके। अपील समिति ने माना कि जाँच प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोटेशन के सही न होने के संबंध में यह एक गंभीर स्थिति वाला निष्कर्ष था। अपील समिति द्वारा सभी सिद्ध आरोपों के संबंध में संहितागत औपचारिकताओं और प्रक्रिया का पालन न करने के पहलू की फिर से जाँच की गई - अपील समिति ने नोट किया कि भवन निर्माण कार्यों में निर्माण समिति को शामिल किए बिना मैसर्स भारद्वाज एसोसिएट्स को 06 में से 05 ठेके देने के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से स्वीकृति का एक तत्व था और याचिकाकर्ता के खिलाफ़ आरोप स्वीकृति और अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर विधिवत साबित हुए थे।

च) अपील समिति ने याचिकाकर्ता के तर्कों पर विचार किया कि नियमों के उल्लंघन के लिए अकेले उसे ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और पाया कि अपीलकर्ता यह कहकर उल्लंघनों में शामिल होने के संबंध में अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता कि उसके अधीनस्थ भी नियमों में निर्धारित तात्कालिकता को प्रमाणित किए बिना सामान्य खरीद प्रक्रिया पालन न करने के निर्णयों में शामिल थे। सामान्य वित्तीय नियम अनिवार्य थे और याचिकाकर्ता द्वारा जिस तरह से खरीदारी की गई वह अभूतपूर्व थी। कोई भी खरीद प्रक्रिया कोटेशन प्राप्त होने से पहले भी ऑर्डर देने की अनुमति नहीं दे सकती। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने ऑर्डर दे दिया था और कोटेशन प्राप्त होने से पहले ही माल

खरीद लिया गया था। समिति ने कहा कि चूँकि कॉलेज सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान पर निर्भर था और दिल्ली सरकार के विशिष्ट परिपत्र ने अनुदान का उपयोग करने के तरीके को स्पष्ट कर दिया था और कॉलेज में किसी भी प्राधिकरण को सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अलावा अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करने के लिए अधिकृत या शक्ति नहीं दी जाएगी। समिति ने पाया कि याचिकाकर्ता खरीद के लिए नियमों और औपचारिक औपचारिकताओं के अनुपालन में बार-बार और लगातार विचलन और चूक को उचित साबित में सक्षम नहीं था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में कोटेशन आमंत्रित किए बिना ही खरीदारी की गई थी।

छ) अपील समिति ने याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए दोषपूर्ण/अस्पष्ट आरोपों के विशिष्ट उदाहरणों पर विचार किया और पाया कि एक मामले में आरोप पत्र में दी गई तिथि 15 नवंबर, 1996 थी, जबकि दस्तावेज़ों में तिथि 6 नवंबर, 1996 दिखाई गई थी। समिति ने पाया कि जाँच समिति ने सही तिथि 6 नवंबर, 1996 को स्वीकार किया था और आरोप-पत्र की यह गलती कोई महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि याचिकाकर्ता को दिए गए दस्तावेज़ों में सही तिथि थी। एक अन्य मामले में आरोप में भुगतान की गई राशि 3472/- रुपये दिखाई गई जबकि भुगतान की गई वास्तविक राशि 34720/- रुपये थी। जाँच रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया और पाया गया कि यह गलती बस एक टंकण संबंधी गलती थी और

इससे याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। अन्यथा भी, जिन दस्तावेज़ों और चेकों से भुगतान किया गया था, उनमें तिथि और राशि अंकित थी। हालाँकि, यह पाया गया कि इस मामले में आरोप साबित हुआ कि वाटर कूलर की आपूर्ति के चालान के साथ-साथ भुगतान के लिए चेक पर कोटेशन जारी होने की तिथि से पहले की तिथि अंकित थी और जाँच प्राधिकरण ने पाया कि कोटेशन दिखावे के लिए लगाए गए थे और वास्तव में कोटेशन आमंत्रित किए जाने से पहले ही ऑर्डर दे दिया गया था। अपील समिति ने कहा कि कथित दोषों का जाँच प्राधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही मूल्य में त्रुटि के कारण उल्लंघन की गंभीरता को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए अन्य दोषों के संबंध में अपील समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि बताए गए दोष सतही थे और जाँच के परिणाम को प्रभावित नहीं करते थे। एक मामले में बिल की राशि 32450/- रुपये थी जबकि आरोप पत्र में इसे 1,32,450/- रुपये दर्शाया गया था। जाँच प्राधिकरण ने स्वयं इस गलती को देखा और बताया और आरोप पर सही परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया। वास्तव में, याचिकाकर्ता के खिलाफ़ आरोप राशियों के संबंध में नहीं थे, बल्कि बिना कोटेशन आमंत्रित किए और बिना टेंडर/कोटेशन खोले या क्रय समिति की भागीदारी के खरीदारी करने के सामान्य वित्तीय नियमों से विचलन के संबंध में थे। इसलिए अपील समिति ने निष्कर्ष निकाला कि

आरोपों में दोषों के संबंध में याचिकाकर्ता का बचाव झूठा था और याचिकाकर्ता आरोपों में तथाकथित दोषों से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं था।

ज) विश्वविद्यालय अध्यादेश या सरकार के प्रासंगिक नियमों की प्रयोज्यता के बारे में याचिकाकर्ता के तर्क के संबंध में, अपील समिति ने कहा कि जहाँ भी विश्वविद्यालय अध्यादेश या नियम मौन हैं, सरकारी नियम और निर्देश सामान्य वित्तीय नियमों के साथ-साथ लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जुर्मानों के संबंध में कें.सि.से. (वर्गी.नि.अ.) नियमों के संबंध में भी लागू होंगे। अध्यादेश XII ने केवल शिक्षक या प्रधानाचार्य की नियुक्ति के मनमाने निर्धारण को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं। अध्यादेश में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि वैध कारणों से अन्य जुर्माने नहीं लगाए जा सकते।

झ) जाँच रिपोर्ट और साक्ष्य की वैधता के संबंध में, अपील समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जाँच प्राधिकरण ने साबित किए गए दस्तावेज़ों की सीमा को छोड़कर, साक्षियों के साक्ष्य को नज़रअंदाज़ कर दिया था और सिद्ध आरोपों के संबंध में लगभग पूरी तरह से दस्तावेज़ी सबूतों पर निर्भर किया था और साक्षियों के साक्ष्य पर केवल तब निर्भर किया था जब इसकी पूरी तरह से दस्तावेज़ी साक्ष्यों से पुष्टि हो गई थी। अपील समिति ने उदाहरण के तौर पर कुछ आरोपों पर चर्चा की। आरोप सं.3.9.5 दो (2) लाख रुपये से अधिक की लागत वाली

मेज और कुर्सियों की खरीद से संबंधित है, जहाँ मुख्य आरोप यह था कि चार में से तीन कोटेशन वास्तविक नहीं थे। रिकॉर्ड में पाया गया कि माल का बिल 20 अक्टूबर, 1995 का था, जबकि कोटेशन बाद में 8 नवंबर 1995 को अर्थात् माल पहले ही खरीदे जाने के बाद खोले गए थे। क्रय समिति या शासी निकाय की कोई मंज़ूरी नहीं थी और अनिवार्य खुली निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। जाँच प्राधिकरण द्वारा इस आरोप को सिद्ध माना गया और अपील समिति ने निष्कर्ष निकाला कि जाँच प्राधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कुछ भी मनमाना नहीं था। आरोप सं. 3.11.5 के मामले में, यह आरोप मैसर्स संजय डीज़ल्स से 2 लाख रुपये में जनरेटर सेट की खरीद से संबंधित था, मुख्य आरोप यह था कि तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं थे और कोई खुली निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, क्रय समिति से कोई मंज़ूरी नहीं ली गई थी। जाँच रिपोर्ट से पता चला कि इन सामानों का बिल 31 मार्च, 1998 की तिथि का था और उसी दिन स्वीकृत किया गया था और सामान उसी दिन स्टॉक में प्राप्त हुआ था और आपूर्तिकर्ता से कोटेशन 27 मार्च, 1998 की तिथि के थे। जाँच प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि खरीद कोटेशन आमंत्रित किए बिना की गई थी। इस मामले में नियमों के तहत खुली निविदा पूछताछ की आवश्यकता थी, क्योंकि खरीद 50,000/- रुपये से अधिक मूल्य की थी और याचिकाकर्ता के खिलाफ़ नियमों के उल्लंघन और संहितागत औपचारिकताओं का

पालन किए बिना खरीदारी करने का आरोप साबित हुआ। अपील समिति ने यह भी पाया कि प्रधानाचार्य द्वारा कोई "तात्कालिकता का प्रमाणपत्र" जारी नहीं किया गया था। क्रय समिति की भागीदारी के बावजूद, चूक की ज़िम्मेदारी संस्था के प्रमुख अर्थात् प्रधानाचार्य से नहीं हटाई जा सकती, जब तक कि कार्यवाही के रिकॉर्ड के सामने यह स्पष्ट न हो कि उसे गुमराह किया गया था, ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। आरोप सं. 3.11.6 के मामले में, यह आरोप 98,872/- रुपये में माइक्रो प्रोसेसर किट की खरीद से संबंधित है, जिसका भुगतान 31 मार्च, 1998 को किया गया था, तीन में से दो कोटेशन वास्तविक नहीं पाए गए, क्रय समिति इसमें शामिल नहीं थी, किसी खुली निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, शासी निकाय से कोई मंज़ूरी नहीं ली गई थी। जाँच प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला था कि 50,000/- रुपये से अधिक की खरीद के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के तहत आवश्यक औपचारिक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता की यह दलील कि इन औपचारिकताओं का सहारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि धन का उपयोग 31 मार्च, 1998 से पहले किया जाना था, अस्थिर पाया गया। इसी प्रकार आरोप सं. 3.11.13 के मामले में एयर कंडीशनर की खरीद मैसर्स स्नो कूल एयर कंडीशनिंग कंपनी से 1,09,664/- रुपये में की गई थी। जाँच प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि खुली निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और केवल सीमित निविदा जाँच

की गई थी। खुली निविदा पूछताछ की आवश्यकता से विचलन के लिए कोई "तात्कालिकता का प्रमाण पत्र" नहीं दिया गया था और प्रधानाचार्य को उसकी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता था। अपील समिति ने इसी तरह अन्य आरोपों पर भी चर्चा की, जिन पर संक्षिप्तता के कारण यहाँ चर्चा नहीं की जा रही है और अपील समिति ने पाया कि जाँच प्राधिकरण द्वारा सिद्ध माने गए सभी आरोप सही साबित हुए हैं और वह जाँच प्राधिकरण की रिपोर्ट से सहमत है। अपील समिति ने पाया कि जाँच प्राधिकरण ने साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया था और निष्पक्ष और उचित निष्कर्ष दिया था। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने खरीद आदेश पर अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथि नहीं डाली थी और दोष अपने अधीनस्थों पर मढ़ दिया था। चूँकि उन्होंने ये आरोप लगाए थे, इसलिए कामकाज के आधिकारिक क्रम में रखे गए रिकॉर्ड में छेड़छाड़ को साबित करने की ज़िम्मेदारी याचिकाकर्ता पर थी। अपील समिति ने पाया कि वह कथित छेड़छाड़ के समर्थन में कोई ठोस सबूत देने में सक्षम नहीं थे। अपील समिति ने जाँच प्राधिकरण के निष्कर्षों में कुछ भी गलत नहीं पाया और निम्नानुसार कहा:

> *क. जाँच ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से की गई थी, साक्ष्यों का अधिक सावधानी से मूल्यांकन किया गया और जहाँ भी संभव हो, आरोपित अधिकारी को संदेह का लाभ दिया गया।*

ख. जाँच प्राधिकरण द्वारा आरोप पत्र की खामियों पर ध्यान दिया गया और जिस हद तक आरोपों को साबित माना गया, उसके संबंध में अपीलार्थी के बचाव पर उनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

ग. जाँच रिपोर्ट में कोई विरोधाभास नहीं है, जिससे आरोपों को साबित करने के संबंध में अलग-अलग निष्कर्ष निकाले जा सकें। जो आरोप साबित हुए, वे सही साबित हुए।

7. अपील समिति ने याचिकाकर्ता को कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद से हटाने का निर्णय बरकरार रखा।

8. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ़ की गई जाँच में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि जाँच किन नियमों के तहत की गई थी, याचिकाकर्ता केवल सेवा संविदा और दिल्ली विश्वविद्यालय नियमों द्वारा शासित हो रहा था, सामान्य वित्तीय नियमों की प्रयोज्यता उसकी सेवा शर्तों का हिस्सा नहीं थी और उसे सामान्य वित्तीय नियमों के उल्लंघन का दोषी ठहराना कदाचार नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने राजेश्वर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य 1990(1) सर्विसेज़ लॉ रिपोर्टर 24 पर निर्भर किया, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अपीलार्थी के खिलाफ़ कें.सि.से. (वर्गी.नि.अ.) नियम, 1965 के तहत जाँच करना, जो सी.आई.एस.एफ़. नियमों द्वारा शासित था, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था और इस तरह की जाँच के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष और दिया गया दंड अवैध था।

9. मेरा विचार है कि इस निर्णय से याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी। *राजेश्वर सिंह* मामले में याचिकाकर्ता/अपीलार्थी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (कें.औ.सु.ब.) का सदस्य था और कें.औ.सु.ब. के नियमों द्वारा शासित था। जाँच कें.सि.से. (वर्गी.नि.अ.) नियमों के तहत की गई थी और न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि कें.सि.से. (वर्गी.नि.अ.) नियमों के तहत आरोप-पत्र जारी करने और जाँच करने से याचिकाकर्ता के साथ पहले ही पक्षपात हो चुका था।

10. यह स्थापित कानून है कि केवल नियमों या अधिनियम का गलत नाम लेना किसी आदेश या जाँच को रद्द नहीं करेगा। देखने वाली बात यह है कि क्या अधिनियम या नियमों के गलत नाम से संबंधित व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ़ जाँच कें.सि.से. (वर्गी.नि.अ.) नियमों के उल्लंघन के संबंध में नहीं की गई थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कें.सि.से. (वर्गी.नि.अ.) नियम प्रक्रिया का पालन किया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ़ निष्पक्ष जाँच की गई थी। वास्तव में यह जाँच याचिकाकर्ता के खिलाफ़ वर्षों से कॉलेज के लिए की गई खरीदारी में संहितागत औपचारिकताओं के उल्लंघन और सामान्य वित्तीय नियमों का पालन नहीं करने के लिए की गई थी। याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य होने के नाते संबंधित नियमों के तहत निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन करने के लिए ज़िम्मेदार माना गया

था और इस उल्लंघन को दस्तावेज़ों और साक्ष्यों के आधार पर जाँच प्राधिकरण के समक्ष साबित करने की माँग की गई थी। किसी भी परिस्थिति में केवल कें.सि.से. (वर्गी.नि.अ.) नियम बताने से याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता, जिसे केवल यह दिखाना था कि उसने नियमों के अनुसार कार्य किया था।

11. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि सामान्य वित्तीय नियम याचिकाकर्ता की सेवा शर्तों का हिस्सा नहीं थे और याचिकाकर्ता केवल उसके सेवा संविदा द्वारा शासित था, फिर से एक गलत तर्क है। याचिकाकर्ता के सेवा संविदा में यह नहीं कहा गया है कि प्रधानाचार्य के रूप में अपने विभिन्न कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाएगा। किसी पद पर नियुक्त कोई भी कर्मचारी/कार्यकारी अधिकारी/प्रधानाचार्य या प्रशासनिक अधिकारी, अपने सेवा संविदा द्वारा शासित होने के अलावा, उस व्यवसाय के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए भी बाध्य है जिसे वह संचालित करना चाहता है। यदि कोई प्रधानाचार्य कॉलेज का प्रमुख है, तो वह कॉलेज के प्रशासन के लिए बने विभिन्न नियमों और विनियमों से बँधा हुआ है। अलग-अलग प्रकृति की नौकरी के लिए ये नियम-कायदे अलग-अलग हो सकते हैं। यदि वह खरीदारी में शामिल है, तो वह सामग्री की खरीद के लिए दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य वित्तीय नियमों और संहितागत औपचारिकताओं के नियमों और विनियमों से बंधा

हुआ है। वह यह अभिवाक् नहीं दे सकता कि चूँकि ये सामान्य वित्तीय नियम उसके सेवा संविदा का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वह सामान्य वित्तीय नियमों से बाध्य नहीं था। यदि इस तर्क को मान लिया जाता है तो शायद किसी भी कर्मचारी पर कदाचार या नियमों के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है क्योंकि कर्मचारियों को जो नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं वे केवल नौकरी के लिए विशिष्ट सेवा शर्तों को प्रदान करते हैं। नियुक्ति पत्र प्रत्येक प्रशासनिक ज़िम्मेदारी के संबंध में लागू नियमों का उल्लेख नहीं करते हैं जिन्हें एक व्यक्ति को निर्वहन करना होता है। तब तो कोई व्यक्ति यह तर्क भी दे सकता है कि उसकी सेवा शर्तों में यह नहीं लिखा है कि वह भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) या अन्य दंड विधियों से बँधा होगा और कह सकता है कि वह भ्रष्ट और अत्याचारी होने के लिए स्वतंत्र था और विद्यार्थियों को चोट पहुँचाने के लिए स्वतंत्र था क्योंकि यह उसकी सेवा शर्तों का हिस्सा नहीं था कि वह भा.दं.सं. से बँधा हुआ था। इसलिए, मेरे विचार में याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वह सामान्य वित्तीय नियमों से बाध्य नहीं था या वह खरीदारी करने के लिए संहितागत औपचारिकताओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं था या कि दिल्ली सरकार के पास यह निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का उपयोग सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा, एक गलत तर्क है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

12. याचिकाकर्ता ने इस तर्क पर ज़ोर देने के लिए सवाई सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 995 पर निर्भर किया कि उसके खिलाफ़ लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे और आरोपों को निष्पक्ष रूप से पूरा करना कठिन था और इसलिए इन आरोपों के आधार पर की गई जाँच निष्प्रभावी हो गई। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम ए वेंकट रायडू 2007(1) एस.सी.सी. 338 पर भी निर्भर किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> 9. *हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। यह प्राकृतिक न्याय का स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी जाँच में किसी सामग्री का उपयोग करने की माँग की जाती है, तो उस सामग्री की प्रतियाँ उस पक्ष को प्रदान की जानी चाहिए जिसके खिलाफ़ ऐसी जाँच की जा रही है। आरोप 1 में बताया गया है कि प्रत्यर्थी ने सरकार द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन किया है। हालाँकि, आरोप 1 में इन आदेशों का कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आरोप-पत्र अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि विशिष्ट होना चाहिए। प्राधिकरण को सरकारी आदेश की तिथि आदि का उल्लेख करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सरकार के उक्त सरकारी आदेशों या निर्देशों की प्रतियाँ भी जाँच अधिकारी के समक्ष नहीं रखी गईं। इसलिए, आरोप 1 विशिष्ट नहीं था और इसलिए उस आरोप के आधार पर अपराध का कोई निष्कर्ष तय नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि*

उच्च न्यायालय ने पाया है, प्रत्यर्थी ने केवल अपने पूर्ववर्तियों द्वारा पहले से की गई जमा राशि का नवीनीकरण किया। इसलिए, हमारी राय है कि आरोपित अपराध के लिए प्रत्यर्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

13. इस निर्णय से याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी। अपील समिति ने प्रत्येक आरोप की जाँच की थी जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि आरोप अस्पष्ट था। इस क्रम में पिछले पैराग्राफ़ में, उसके तर्क पर अपील समिति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह की गई अस्पष्टता की प्रकृति बताते हुए पुन: प्रस्तुत किया गया है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अनावश्यक रूप से यह याचिका उठा रहा है। याचिकाकर्ता इस मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहा है कि आरोप-पत्र में उल्लिखित तिथि या राशि में टंकण संबंधी त्रुटि के कारण वह कैसे पूर्वाग्रहग्रस्त हो गया, जब उसे दिए गए दस्तावेज़ों में सही तिथि और सही राशि लिखी थी और इससे भी अधिक जबकि आरोप किसी राशि के दुरुपयोग के संबंध में नहीं था, बल्कि आरोप यह था कि खुली निविदाएँ आमंत्रित किए बिना और यहाँ तक कि सीमित निविदाएँ खोले बिना या सीमित निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही उसके द्वारा खरीदारी की गई थी या उसने बाद में निविदाओं में हेरफेर किया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ़ संहितागत औपचारिकताओं का पालन न करने और सामान्य वित्तीय नियमों का अनुपालन न करने के आरोपों के संबंध में आरोप-पत्र अधिक विशिष्ट थे। अपील

समिति द्वारा निकाला गया निष्कर्ष ठोस आधारों पर निर्भर है और इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के विपरीत नहीं माना जा सकता है।

14. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि जिस कदाचार के लिए उसे सेवा से हटाया गया था, उसे अपील समिति या जाँच प्राधिकरण द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। उसने कहा कि कदाचार की व्याख्या नियमों के अनुरूप की जानी चाहिए। अपील समिति ने 'कदाचार' को परिभाषित नहीं किया था और यह भी विनिर्णय नहीं सुनाया था कि याचिकाकर्ता का आचरण 'कदाचार' की परिभाषा में ठीक बैठता है या नहीं। याचिकाकर्ता ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम राम सिंह, पूर्व कांस्टेबल ए.आई.आर 1992 एस.सी. 2188 पर निर्भर किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा था:

> *4. कदाचार को ब्लैक लॉ डिक्शनरी के छठे संस्करण में पृष्ठ 999 पर इस प्रकार परिभाषित किया गया है: -*
>
> *"कार्रवाई के कुछ स्थापित और निश्चित नियम का उल्लंघन, निषिद्ध कार्य, कर्तव्य से विमुखता, विधिविरूद्ध व्यवहार, चरित्र में दुराग्रही, अनुचित या गलत व्यवहार, इसके पर्यायवाची या दुराचार, दुष्कर्म, दुर्व्यवहार, अपचारिता, अनुचितता, कुप्रबंधन, अपराध, लेकिन उपेक्षा या असावधानी नहीं।"*
>
> *कार्यालय में दुर्व्यवहार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:*

"किसी लोक अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के कर्तव्यों के संबंध में कोई भी विधिविरूद्ध व्यवहार, चरित्र में दुराग्रही। इस शब्द में ऐसे कार्य शामिल हैं जिन्हें करने का पदधारी को कोई अधिकार नहीं था, अनुचित तरीके से किए गए कार्य, और कार्य करने के सकारात्मक कर्तव्य के बावजूद कार्य करने में विफलता।"

पी.रामनाथ अय्यर के द लॉ लैक्सिकन के पुनर्मुद्रण संस्करण 1987 के पृष्ठ 821 पर 'कदाचार' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

"कदाचार शब्द का तात्पर्य गलत इरादे से है, न कि केवल निर्णय में त्रुटि से। कदाचार आवश्यक रूप से नैतिक अधमता से जुड़े आचरण के समान नहीं है। कदाचार शब्द एक सापेक्ष शब्द है, और इसकी व्याख्या विषय वस्तु और उस सामग्री के संदर्भ में की जानी चाहिए जिसमें यह शब्द आता है, अधिनियम या कानून के दायरे को ध्यान में रखते हुए जिसका अर्थ लगाया जा रहा है। कदाचार का शाब्दिक अर्थ गलत आचरण या अनुचित आचरण है। सामान्य बोलचाल में, कदाचार को आचरण के एक विशिष्ट, स्थापित नियम के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कार्य करने वाले को आवश्यकता के अलावा सभी विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है, इसके विपरीत, उपेक्षा, लापरवाही और अकुशलता आचरण के एक सामान्य, स्थापित नियम का उल्लंघन है जिसमें कार्य करने वाले को कुछ विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। कदाचार निश्चित विधि

का उल्लंघन है; अनिश्चितकालीन विधि के तहत लापरवाही या विवेक का दुरुपयोग। कदाचार एक निषिद्ध कार्य है; लापरवाही, किसी कार्य का निषिद्ध गुण है, और आवश्यक रूप से अनिश्चित है। कार्यालय में कदाचार को किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा विधिविरूद्ध व्यवहार या उपेक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे किसी पक्ष के अधिकार प्रभावित हुए हैं।"

5. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 'कदाचार' शब्द का हालाँकि सटीक परिभाषा में वर्णन सक्षम नहीं है, लेकिन इसका प्रतिबिंब संदर्भ, इसके प्रदर्शन में अपराध और अनुशासन और कर्तव्य की प्रकृति पर इसके प्रभाव से अपना अर्थ प्राप्त करता है। इसमें नैतिक अधमता शामिल हो सकती है, यह अनुचित या गलत व्यवहार होना चाहिए; विधिविरुद्ध व्यवहार, चरित्र में दुराग्रही; निषिद्ध कार्य, कार्रवाई के स्थापित और निश्चित नियम या आचार संहिता का उल्लंघन, लेकिन केवल निर्णय की त्रुटि नहीं, कर्तव्य के प्रदर्शन में उपेक्षा या लापरवाही, जिस कार्य की शिकायत की गई है उसमें निषिद्ध गुणवत्ता या चरित्र है। इसके दायरे को विषय-वस्तु और उस संदर्भ के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें यह शब्द आता है, कानून के दायरे और सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसे वह पूरा करना चाहता है। पुलिस सेवा एक अनुशासित सेवा है और इसमें सख्त अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में

ढिलाई से सेवा में अनुशासन समाप्त हो जाता है जिससे विधि एवं व्यवस्था के रखरखाव पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

15. सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि 'कदाचार' शब्द में ऐसे कार्य शामिल हैं जिन्हें करने का कार्यालय धारक के पास कोई अधिकार नहीं है या कार्य अनुचित तरीके से किया गया है या अधिकारी नियमों के अनुसार कार्य करने के सकारात्मक कर्तव्य के सामने कार्य करने में विफल रहता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता कॉलेज का प्रधानाचार्य था। दिल्ली सरकार के परिपत्र ने यह देखना कॉलेज के प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी बना दी कि सरकार द्वारा दिया गया अनुदान सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार खर्च किया जाए। यह मानते हुए कि कोई सामान्य वित्तीय नियम मौजूद नहीं थे और कॉलेज के प्रधानाचार्य को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार खरीदारी करनी थी जो निष्पक्ष और न्यायसंगत होगी, तो क्या यह कॉलेज के प्रधानाचार्य को अपने विवेक से मनमाने ढंग से किसी से कोटेशन आमंत्रित बिना सारी खरीदारी करने का अधिकार देता है? भले ही सामान्य वित्तीय नियमों द्वारा कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई हो, तब भी खरीद के मामलों के शीर्ष पर मौजूद कोई भी समझदार व्यक्ति, यदि निष्पक्षता के बारे में चिंतित है, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी संख्या में कोटेशन आमंत्रित करेगा कि उसे कॉलेज की खरीदारी के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य पर चीज़ें मिल रही है। कोटेशन आमंत्रित करने की प्रक्रिया

का पालन किया जाता है ताकि यह रिकॉर्ड रखा जा सके कि विभिन्न डीलरों द्वारा क्या कीमत उद्धृत की गई थी और किस कीमत पर सामान खरीदा गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने इस कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में अपने पूरे करियर में खरीदारी की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कुछ मामलों में, उसने माल पहले खरीदा और कोटेशन बाद में खोले गए, कुछ मामलों में, कोई कोटेशन आमंत्रित ही नहीं किए गए थे और कुछ मामलों में यह छिपाने के लिए कि कोटेशन मँगाए जा रहे हैं, माल खरीदा गया, बिलों का भुगतान किया गया, फिर स्टॉक रजिस्टर में माल की प्रविष्टियाँ की गईं और उसके बाद यह दिखाने के लिए कि कोटेशन आमंत्रित किए गए थे, कोटेशन खोले गए। प्रधानाचार्य ने इतनी बुद्धिमानी दिखाई कि उन्होंने अपने हस्ताक्षरों के नीचे कोई तिथि नहीं लिखी। यदि याचिकाकर्ता इतना ईमानदार व्यक्ति था और कॉलेज और विद्यार्थियों के लिए इतना चिंतित था, जैसा कि वह होने का दावा करता है, तो कोई भी यह नहीं समझ पाएगा कि उसने खरीद से संबंधित सभी दस्तावेज़ों पर अपने हस्ताक्षर के नीचे कोई तिथि क्यों नहीं लिखी। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रधानाचार्य को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हस्ताक्षर के नीचे तिथि डालना एक महत्वपूर्ण कारक था। इससे केवल यह पता चलता है कि प्रधानाचार्य जानबूझकर अपने हस्ताक्षरों के नीचे तिथि नहीं डाल रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि उनके द्वारा और उनके अधीन व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा था,

वह नियमों के अनुसार नहीं था, और चीज़ों को अस्पष्ट रखना (हस्ताक्षरों के नीचे तिथि न डालना) अन्यथा उनके लिए मददगार ही होगा। कोई भी यह नहीं समझ पाता कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। कोटेशन आमंत्रित किए जाने से पहले ही माल क्यों खरीदा गया और बिलों का भुगतान क्यों किया गया। इस सबका स्पष्टीकरण याचिकाकर्ता द्वारा अपील समिति के समक्ष, या इस न्यायालय के समक्ष, या जाँच प्राधिकरण के समक्ष बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता केवल यह तर्क दे रहा है कि उसने कॉलेज के सर्वोत्तम हित में कार्य किया। न्यायालय यह समझने में विफल रहता है कि खरीदारी करने से पहले विभिन्न डीलरों से कोटेशन न आमंत्रित करके कॉलेज का सर्वोत्तम हित कैसे पूरा किया जा सकता है, और पूरे वर्ष बजट का उपयोग न करने और केवल वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह के भीतर बिना किसी औपचारिकता का पालन किए खरीदारी करने से कैसे सर्वोत्तम हित पूरा हुआ, और यदि सामान की तत्काल आवश्यकता थी और औपचारिकताओं को नज़रअंदाज़ किया ही जाना था तो प्रधानाचार्य द्वारा "तात्कालिता प्रमाणपत्र" जारी न करने से कॉलेज का सर्वोत्तम हित कैसे पूरा हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा निर्भर किए गए निर्णय को देखते हुए, सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के ये सभी उल्लंघन और प्रधानाचार्य की ओर से निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के उल्लंघन और परिस्थितियों की तात्कालिकता कदाचार की श्रेणी में आते हैं। भले ही अपील समिति ने कदाचार

को परिभाषित नहीं किया है, अपील समिति के निष्कर्षों और जाँच प्राधिकरण के निष्कर्षों के आधार पर कदाचार स्पष्ट रूप से बड़ा है।

16. अधिवक्ता ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता का कोई गलत इरादा नहीं था और कदाचार का तात्पर्य गलत और दुर्भावनापूर्ण इरादा है, न कि केवल निर्णय की त्रुटि। जाँच प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को किसी भी राशि के दुरुपयोग या धन का कोई गलत लाभ प्राप्त करने का दोषी नहीं ठहराया है और याचिकाकर्ता को केवल औपचारिकताओं का पालन न करने के लिए दोषी ठहराया गया था, जो कि एक तकनीकी मामला था और इसके लिए याचिकाकर्ता को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ 'कोषाध्यक्ष' और क्रय समिति के अन्य व्यक्ति भी थे, जो खरीद आदि देख रहे थे।

17. मैं मानता हूँ कि यह तर्क विफल होना चाहिए। किसी व्यक्ति के गलत इरादे का हमेशा व्यक्ति के कृत्यों से पता लगाया जाता है न कि व्यक्ति के शब्दों से। जाँच प्राधिकरण धन के दुरुपयोग या उच्च दरों पर की गई खरीदारी या निम्न गुणवत्ता वाले सामान या क्या सामान कॉलेज के सर्वोत्तम हित में खरीदा गया था या नहीं, के आरोप पर आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ़ इस संबंध में कोई आरोप नहीं लगाए गए थे। जाँच प्राधिकरण केवल उन आरोपों पर आगे बढ़ा था जो याचिकाकर्ता के खिलाफ़ तैयार किए गए थे। याचिकाकर्ता के

खिलाफ़ आरोप कॉलेज के लिए खरीदी गई सेवाओं और सामानों को लेने के मामले में सामान्य वित्तीय नियमों के उल्लंघन में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कृत्यों के संबंध में थे और ये आरोप साबित हुए हैं। याचिकाकर्ता के गलत इरादे का इस तथ्य से अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी अनुमोदनों पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद याचिकाकर्ता ने खरीदारी की मंज़ूरी की वास्तविक तिथि को अस्पष्ट बनाए रखने के लिए जानबूझकर अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथियाँ नहीं लिखीं। इसलिए मैं मानता हूँ कि याचिकाकर्ता का यह तर्क विफल होना चाहिए।

18. यह स्थापित विधि है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। यह न्यायालय अधिकरण/अपील समिति के आदेश के खिलाफ़ अपील के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता के सभी तर्क अपील समिति के आदेश के खिलाफ़ अपील की प्रकृति में हैं और मैं मानता हूँ कि यह न्यायालय पूरी सामग्री पर पुनर्विचार करने के बाद अपील समिति द्वारा पारित अधिनिर्णय को फिर से लिख नहीं सकती है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन किया गया था, जाँच को पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया गया था, जाँच प्राधिकरण और अपील समिति ने पूरे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य किया है।

याचिकाकर्ता को अपने मामले को प्रस्तुत करने और खुद का बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

19. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि उसे हटाने का दंड उसके खिलाफ़ साबित हुए आरोपों के लिए पूरी तरह से असंगत था। उनके खिलाफ़ साबित हुए आरोप सामान्य वित्तीय नियमों के तकनीकी उल्लंघन के थे और उनके निष्कासन का दंड बहुत कठोर दंड था।

20. प्रधानाचार्य का पद भरोसे का पद है। संस्थान का प्रमुख होने के नाते प्रधानाचार्य से निष्पक्ष रूप से ज़िम्मेदार और भरोसेमंद तरीके से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और यदि प्रधानाचार्य के कृत्यों और कार्यों के कारण शासी निकाय का प्रधानाचार्य पर से भरोसा उठ जाता है और शासी निकाय ने जाँच करने और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्रधानाचार्य को पद से हटा दिया है, तो न्यायालय प्रधानाचार्य को दिए गए दंड पर अधिनिर्णय नहीं दे सकता है और प्रधानाचार्य की सेवाओं को शासी निकाय पर नहीं थोप सकता है। डॉ. एस.बी. दत्त बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1959 एस.सी.आर. 1236 के मामले में, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ के एक अधिनिर्णय को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह घोषित करना कि श्री दत्त अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर थे, विधि के विपरीत था क्योंकि कोई भी न्यायालय

उन्हें ऐसी राहत नहीं दे सकता था या देता। उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि यह घोषणा व्यक्तिगत सेवा की संविदा के एक विशिष्ट प्रवर्तन के समान है जिसे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 21 द्वारा निषिद्ध किया गया था और इसलिए अधिनिर्णय के दौरान एक त्रुटि का खुलासा हुआ। उच्च न्यायालय के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि यह उच्च न्यायालय के व्यक्त विचार से पूरी तरह सहमत है और व्यक्तिगत सेवा की संविदा को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 21 खंड (ख) में विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

21. टी.एन.सी.एस. कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम के. मीराबाई 2006(2) एस.एस.सी. 255 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित था। सहानुभूति या उदारता को एक कारक के रूप में लेना अस्वीकार्य है। भरोसे की हानि प्राथमिक कारक थी न कि दुरुपयोग की गई धनराशि। चूँकि प्रत्यर्थी कर्मचारी को कॉर्पोरेशन के धन के दुरुपयोग का दोषी पाया गया था, इसलिए कॉर्पोरेशन द्वारा ऐसे कर्मचारी पर विश्वास खोने में कुछ भी गलत नहीं था।

22. केनरा बैंक बनाम वी.के. अवस्थी (2005) 6 एस.सी.सी. 321 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दंड की मात्रा का अनुमान लगाना नियमित मामला नहीं हो सकता। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सिद्ध आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि प्रत्यर्थी कर्मचारी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और परिश्रम से निभाने में विफल रहा और उसके कार्य बैंक के हित के लिए हानिकारक थे। कर्मचारी को बर्खास्त करने के बैंक के निर्णय में कोई खामी नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए दंड की मात्रा पर एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेश को रद्द कर दिया। जनता बाज़ार (साउथ कनारा सेंट्रल कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड) और अन्य बनाम सचिव, सहकारी नौकरारा संघ और अन्य (2000) 7 एस.सी.सी. 517 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही वित्तीय अनियमितता बहुत छोटी राशि की हो, लेकिन इसका एकमात्र दंड बर्खास्तगी है।

23. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता को दिए गए दंड को याचिकाकर्ता के खिलाफ़ साबित हुए कदाचार के अनुपात से अधिक नहीं माना जा सकता है। मुझे याचिका में कोई बल नहीं दिखता। याचिका एतद्द्वारा अस्वीकार की जाती है।

न्या. शिव नारायण ढींगरा

04 सितंबर, 2009

वी.एन.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*